अक्टूबर में शुरू होने वाले पेराई सीजन से पहले साफ पॉलिसी की मांग

गन्ने की कीमत पर UP की मिलें कर सकती हैं शटडाउन

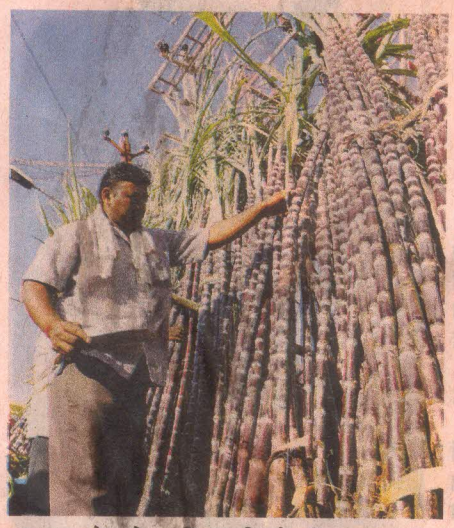

- **उत्तर प्रदेश** में अभी तक मिलों की आमदनी से गन्ने की कीमतों को नहीं जोड़ा गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस तरह की पॉलिसी लागू की जा चुकी है
- **यूपी सरकार** की ओर से तय 280 रुपये प्रति क्विंटल का दाम देश में सबसे अधिक है
- **शुगर इंडस्ट्री** का मानना है कि अगर रंगराजन पैनल के फॉर्मूले के मुताबिक गन्ने की कीमतों को लिंक किया जाए तो राज्य में इसके दाम घटकर 235-240 रुपये प्रति क्विंटल पर आ जाएंगे

[माधवी सैली & नई दिल्ली]

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें अक्टूबर में शुरू होने वाले पेराई के अगले सीजन से पहले गन्ने की कीमत से जुड़ी पॉलिसी बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा न होने पर वे कामकाज बंद कर देंगी। उत्तर प्रदेश देश में चीनी का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

उत्तर प्रदेश में अभी तक मिलों की आमदनी से गन्ने की कीमतों को नहीं जोड़ा गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस तरह की पॉलिसी लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से तय 280 रुपये प्रति क्विंटल का दाम देश में सबसे अधिक है। राज्य की मिलों पर किसानों का बकाया 7,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इंडस्ट्री को आशंका है कि सितंबर में समाप्त होने मौजूदा सीजन में यह रकम बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगी।

इंडस्ट्री का मानना है कि अगर रंगराजन पैनल के फॉर्मूले के मुताबिक गन्ने की कीमतों को लिंक किया जाए तो राज्य में इसके दाम घटकर 235-240 रुपये प्रति क्विंटल पर आ जाएंगे। 35,000 करोड़ रुपये की शुगर इंडस्ट्री ने किसानों के साथ 75 पर्सेंट रेवेन्यू शेयर करने की सलाह दी है।

बजाज हिंदुस्तान, धामपुर शुगर और डालमिया शुगर सहित कई मिलों ने शिकायत की है कि केन प्राइस लिंकेज फॉर्मूला न होने से इंडस्ट्री 'गैर वाजिब तरीके से तय किया गया' गन्ने का दाम चुकाने की स्थिति में नहीं है। मिलों ने सरकार की ओर से तंग किए जाने का आरोप भी लगाया है। एक मिल मालिक ने कहा कि कंपनियां अपनी फैक्टरियों में मेंटेनेंस का काम नहीं करवा पा रहीं क्योंकि बकाया पेमेंट को लेकर पुलिस ने सीनियर मैनेजमेंट के खिलाफ लगभग 50 एफआईआर दर्ज की हैं। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के एक ऑफिशियल ने बताया, 'हम सोमवार-मंगलवार को सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद अगले कदम के बारे में फैसला किया जाएगा। हम फाइनेंशियल तौर पर बहुत खराब स्थिति में हैं और हमें बिजनेस में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा।'

इंडस्ट्री ने इस सीजन में चौथी बार यह मुद्दा उठाया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने कहा, 'पिछले चार सीजन से उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें नुकसान उठा रही हैं। अगर राज्य में महाराष्ट्र जैसी एक संतुलित पॉलिसी नहीं होगी तो हम कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे।'

मिलों के दावे पर सवाल

क्रॉप एनालिस्ट तेजिंदर नारंग का कहना है कि फैक्टरी मालिकों की दलील और जमीनी हकीकत में अंतर है। अगर चीनी मिलें नुकसान उठा रही हैं तो चीनी का प्रॉडक्शन गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका प्रॉडक्शन सरप्लस है।

इस्मा ने देश में मौजूदा शुगर सीजन में प्रॉडक्शन 2.5 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान जताया है। इसके अलावा 80 लाख टन का कैरीओवर स्टॉक भी है। देश में चीनी की सालाना खपत लगभग 2.3 करोड़ टन की है।

Economic Times

4/8/2014